The Economic Times. (Hindi)
26-4-13.

अधिक सप्लाई से शुगर सस्ता हुआ

चीनी की गिरती कीमत से मिलों का मूड खराब

श्रेया जय *नई दिल्ली*

शुगर सेक्टर को डीकंट्रोल करने का केंद्र सरकार का फैसला चीनी मिलों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाया है। मिलों की उम्मीद के उलट, चीनी के दाम डीकंट्रोलिंग के बाद गिरे हैं। इससे मिल मालिक फिक्रमंद हैं। बलरामपुर चीनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किशोर शाह के मुताबिक, 'शुगर इंडस्ट्री लॉस में है। मार्केट की चाल डिमांड-सप्लाई से तय हो रही है। मिलें अगर ज्यादा चीनी बेचती हैं, तो इससे दाम और कम हो सकते हैं। उन्हें किसानों को बकाया पैसा देना है। ऐसे में मिलें चीनी का स्टॉक रोककर नहीं रख सकतीं।'

15 मार्च तक पूरे देश में गन्ना किसानों को मिलों से 12,300 करोड़ रुपए लेने थे। उत्तर प्रदेश में यह रकम सबसे ज्यादा 7,100 करोड़ रुपए है। कर्नाटक में 1,700 करोड़, महाराष्ट्र में 800 करोड़ रुपए और गुजरात में यह 350 करोड़ के करीब है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और यूपी के मुजफ्फरनगर और कानपुर में शुगर ट्रेडर्स का कहना है कि किसानों के बकाया भुगतान के लिए मिलें बड़े पैमाने पर चीनी बेच सकती हैं। कोल्हापुर के शुगर मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि किसानों को पैसा देने के लिए मिलों ने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कीमत पर चीनी बेचनी शुरू कर दी है। मार्केट में शुगर की डिमांड जितनी है, उससे कहीं ज्यादा इसकी सप्लाई है। कानपुर मंडी में सबसे बड़े शुगर ट्रेडर्स में से एक ने कहा, 'यूपी में हालात काफी खराब हैं, क्योंकि यहां स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एसएपी) देश में सबसे ज्यादा है। इस वजह से मिलों को काफी लॉस हो रहा है। राज्य के कई हिस्सों से ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि किसान मिलों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यहां तक कि शुगर मिल एग्जिक्यूटिव्स को धमकाया जा रहा है।'

किसानों को देना है पेमेंट

किसानों को पैसा देने के लिए मिलों ने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम कीमत पर चीनी बेचनी शुरू कर दी है

एसएपी राज्य तय करता है। गन्ने के लिए यह कीमत मिलें राज्य के किसानों को देती हैं। इसके लिए केंद्र भी सुझाव देता है, जिसे एफआरपी कहते हैं। अक्सर राज्य सरकारें गन्ने की कीमत इससे ज्यादा रखती हैं। इस शुगर सीजन (सितंबर 2012 से अक्टूबर 2013) के लिए एफआरपी 170 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं, यूपी ने एसएपी 280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। हरियाणा और पंजाब में एसएपी 240 रुपए है। तमिलनाडु में यह 225 रुपए और महाराष्ट्र में 190 रुपए है।